

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1923/2014

लखनलाल

—अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
2. लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सिवरेज प्रबन्धक मण्डल, कोटा।
—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.04.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेन्द्र सोनगरा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 26.10.2014 (अनुलग्नक-1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी के वेतन से माह नवम्बर, 2014 के वेतन से राशि 3000/-रूपये प्रतिमाह काटने के आदेश दिये गये हैं। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश पूर्व के आदेश दिनांक 09.06.2000 की पालना में जारी किया गया है एवं वह आदेश भी विधि विरुद्ध तरीके से पारित किया गया है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी की नियुक्ति एलडीसी के पद पर दिनांक 24.01.1977 को हुई, जिसकी नियुक्ति शर्तों के अनुसार अपीलार्थी को एक वर्ष के अन्दर टाईपिंग टेस्ट पास करना था। अपीलार्थी ने यह टेस्ट दिनांक 10.03.1978 को पास किया, जिसका इन्द्राज भी सेवापुस्तिका में किया गया। अपीलार्थी का आगे कथन है कि आदेश दिनांक 13.01.1999 से अपीलार्थी की सेवाएं कार्य ग्रहण करने की दिनांक से नियमित की गयी। सन 1994 में अपीलार्थी की पदोन्नति यूडीसी के पद पर की गयी। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1992 को एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 24.01.1995 से स्वीकृत किया गया। तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.11.2010 से देय था, परन्तु उक्त लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया गया। अपीलार्थी को बाद में यह जानकारी प्राप्त हुई कि विभाग ने आदेश दिनांक 09.06.2000 के आदेश द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान के लाभ को निरस्त कर दिया। अपीलार्थी को निरस्तीकरण की कोई सूचना नहीं दी गयी।

उनका कथन है कि जल संसाधन विभाग, राजस्थान द्वारा आदेश दिनांक 02.01.2023 के द्वारा प्रावधान किया गया है कि मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारी जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.04.1978 से 31.12.1984 के मध्य तदर्थ/अस्थाई आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित टंकण/दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात की गई थी उन कर्मचारियों की कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक 3(47) कार्मिक/क-2/84 दिनांक 12.04.1999 के अनुसार उनकी सेवाओं का नियमितकरण उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से किया जाता है। अपीलार्थी ने यह भी कथन किया है कि राजस्थान सरकार ने पूर्व में जारी किये गये चयनित वेतनमान के आदेश को रिव्यू नहीं किये जाने का आदेश भी दिनांक 30.8.2010 को पारित किया। उसके बाद भी को पूर्व में दिये गये प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान के लाभ को रिव्यू कर वसूली निकाली गयी, जो उचित नहीं है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि आदेश दिनांक 24.01.1977 के द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति अस्थायी रूप से 4 माह के लिये राज्य सरकार से देशी (सरप्लस) कर्मचारी उपलब्ध होने अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने तक के लिये की गयी थी, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति नहीं थी। अपीलार्थी ने विभागीय दक्षता परीक्षा दिनांक 01.11.1983 को उत्तीर्ण की। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.1999 को विभागीय आदेश दिनांक 30.05.2000 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। आदेश दिनांक 18.06.1994 द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया। आदेश दिनांक 26.09.1992 एवं आदेश दिनांक 29.10.1996 द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान क्रमशः दिनांक 25.01.1992 एवं 24.01.1995 से तदर्थ नियुक्ति दिनांक 24.01.1977 के आधार पर स्वीकृत किया गया था। जिसे वित्त विभाग के आदेश दिनांक 14.06.1999 की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.06.2000 द्वारा निरस्त कर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण दिनांक 01.11.1983 के आधार पर दिनांक 01.11.1992 एवं 01.11.2001 से प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृति के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश प्रदान कर पूर्व स्वीकृति के कारण हुये अधिक भुगतान की वसूली के आदेश जारी किये गये हैं, जो पूर्णतया नियमानुसार पारित आदेश है। उक्त आदेश दिनांक 09.06.2000 की पालना के अभाव में तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 29.06.2009 एवं 20.8.2010 जारी होने से पूर्व ही बिन्दु संख्या-3 में वर्णितानुसार प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान को आदेश दिनांक 09.06.2000 द्वारा निरस्त किया जा चुका है, जिसकी पालना होनी शेष है। अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित

आदेश में किसी प्रकार से नियमों का उल्लंघन अथवा अनियमितता स्थापित नहीं की गयी है।

3. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
4. अपीलार्थी को पूर्व में उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 24.01.1977 के आधार पर प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ क्रमशः दिनांक 25.01.1992 एवं 24.01.1995 को स्वीकृत किया गया था। इसके पश्चात यह माना गया कि अपीलार्थी ने चूंकि दक्षता परीक्षा दिनांक 01.11.1983 को उत्तीर्ण की। इस आधार पर अपीलार्थी को प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ क्रमशः दिनांक 01.11.1992 एवं 01.11.2001 से देय है। अपीलार्थी को जो पूर्व में उसकी प्रथम नियुक्ति के आधार पर प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान कर दिया गया था, उसे निरस्त करते हुए पूर्व में दिये गये चयनित वेतनमान के लाभ की वसूली की जा रही है, जिसे अपीलार्थी ने इस अपील में चुनौती दी है।
5. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

- "(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?
- (b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?
- (c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?
- (d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?
- (e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the

Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि तदर्थ नियुक्ति की दिनांक से दिये गये चयनित वेतनमान के लाभ की वसूली नहीं की जाए। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी को जो पूर्व में प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है, उसकी वसूली किया जाना उचित नहीं है।
7. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है एवं यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को पूर्व में देय प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान के सम्बन्ध में कोई वसूली नहीं की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)